मुन्सिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे और अन्य

बनाम

अंजली ठुकराल देओ कुमार एवं अन्य

7 मार्च 1989

[एमएम दत्त और टी के थोम्मेन जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-शैक्षिक संस्थान-मेडिकल कॉलेज-प्रवेश-उचित वर्गीकरण के अलावा कोई अन्य प्राथमिकता भेदभावपूर्ण-उचित वर्गीकरण नहीं

बॉम्बे नगर निगम द्वारा बनाए गए नियम-मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश।

नियम 4ए और 5-एमडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज-वार संस्थागत प्राथमिकताएं-बुरा माना गया-योग्यता के अलावा कोई भी प्राथमिकता-भेदभावपूर्ण और अनुचित वर्गीकरण।

बॉम्बे शहर में चार मेडिकल कॉलेज हैं, जो सभी बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। चार में से तीन कॉलेज नगर निगम द्वारा चलाए जाते हैं और एक महाराष्ट्र राज्य द्वारा संचालित और संचालित किया जाता है। नियम 4ए नगर निगम द्वारा बनाया गया है और नियम 5 राज्य सरकार द्वारा

बनाया गया है। सरकार के माध्यम से 18 जून 1971 का संकल्प संबंधित मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित करता है।

उपरोक्त दोनों नियम एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉलेजिएट संस्थागत प्राथमिकता प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कॉलेज में, जिन उम्मीदवारों ने एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण की है। स्नातकोत्तर एम.डी. डिग्री में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए उस कॉलेज एफ से परीक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही उम्मीदवारों ने एमबीबीएस उत्तीर्ण करके उच्च अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हों। परीक्षा। अन्य कॉलेजों से. इस आधार पर कुछ उम्मीदवार जो संबंधित कॉलेजों में एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं थे, जहां से उन्होंने एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण किया था। ऊपर उल्लिखित नियम 4ए और नियम 5 द्वारा प्रदान की गई कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, बॉम्बे शहर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी प्रवेश नहीं दिया गया। उन छात्रों/उम्मीदवारों ने नगर निगम द्वारा बनाए गए उपरोक्त नियम 4ए और नियम 5 की वैधता को चुनौती दी। और राज्य सरकार. उच्च न्यायालय में, कला के उल्लंघन के रूप में। संविधान के 14. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और झटका दिया। विवादित नियम 4ए को समग्र रूप से हटा दें और नियम 5 को जहां तक यह सरकार पर लागू

होता है। मेडिकल कॉलेज को भेदभावपूर्ण और कला का उल्लंघन माना गया। संविधान के 14 और इस प्रकार अमान्य। अतः विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें।

न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ अपीलों को खारिज करते हुए, अभीनिर्धारित किया

जब इन सभी कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय समान है, पाठ्यक्रम, परीक्षा का मानक और यहां तक कि परीक्षक भी समान हैं, तो योग्यता के क्रम को छोड़कर उसी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों के मानक को काफी हद तक प्रभावित करने वाली योग्यता को बाहर करना। ऐसी परिस्थितियों में, कॉलेज-वार संस्थागत प्राथमिकता का समर्थन नहीं किया जा सकता है और, इस न्यायालय ने ऐसी प्राथमिकता को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी है। 1931 एफ-जी] सी

जहां तक शैक्षणिक संस्थानों का सवाल है, जब तक मेधावी उम्मीदवारों को बाहर करने के मजबूत कारण न हों, योग्यता के क्रम के अलावा कोई भी वरीयता डी, कला की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। संविधान के 14. [932 सी-डी]

नियम भेदभावपूर्ण हैं और उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसलिए इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि जिन छात्रों को विवादित नियमों के अनुसार स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उनके प्रवेश में हस्तक्षेप या परेशान नहीं किया जाएगा। [933 ई]

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को अगले वर्ष के लिए स्नातकोत्तर एफ एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कुछ वैकल्पिक तरीकों को अपनाते हुए नियम बनाने का निर्देश दिया है। उक्त निर्देश उच्च न्यायालय के सुझावों की प्रकृति में प्रतीत होते हैं और अपीलकर्ता प्रावधान के अनुरूप बॉम्बे शहर के उक्त चार कॉलेजों में स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। कला। संविधान के 14 और इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में और नियम तैयार करने में, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के सुझावों पर विचार कर सकते हैं। 1934 जी-एच; 935 ए]

डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1984] 3 एस.सी.आर. 942, प्रतिष्ठित

निदामर्ती महेश कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, [1986]

निदामर्ती महेश कुमार बनाम. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, [1986]

एच 2 एस.सी.सी. 534, लागू नहीं.

जगदीश सरन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1980] 2 एस.सी.आर. 831, लागू नहीं।

राजस्थान राज्य एवं अन्य वी. डॉ. अशोक कुमार गुप्ता एवं अन्य, (1989) 1 एस.सी.सी. 93, लागू नहीं.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2792/1988 आदि।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. का क्रमांक 3264/1988 निर्णय और आदेश दिनांक 27.7.1988 से

जी. रामास्वामी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, टी.आर. एंड्यारु- जूना, वी. वी. वाज़े, वी.एम. तारकुडे, डी.एन. मिश्रा, एम. डी. सियोदिया, पिनाकी मिश्रा, पी.एच. पारेख, सुश्री सुनीता शर्मा, ए.एम. खानविलकर, ए.एस. भस्मे, दलवीर भंडारी, विजय थोरात, रायन करंजावाला, श्रीमती माणिक करंजावाला, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वी.डी. खन्ना, रामेश्वर नाथ, बी.आर. अग्रवाल, पी.के. पिल्लई, पी.एन. उपस्थित पक्षों के लिए गुप्ता, श्री नारायण, माधुरी गोखले, प्रांगलिया और एन. नेत्तर।

न्यायालय का निर्णय दत्त, जे. द्वारा सुनाया गया।

इन अपीलों में शामिल मुख्य बिंदु 18 जून को अपने मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के

लिए बॉम्बे नगर निगम द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 4 (ए) की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। 1988 और सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए 18 जून 1971 के सरकारी संकल्प के तहत बनाए गए नियम 5, दोनों नियम एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता प्रदान करते हैं। आक्षेपित निर्णय के द्वारा, उच्च न्यायालय ने उन रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी, जिनमें से ये अपीलें उठी थीं, और आक्षेपित नियम 4(ए) और नियम 5 (उच्च न्यायालय के फैसले में गलत तरीके से नियम 6 के रूप में कहा गया) को अब तक रद्द कर दिया। चूँकि यह बंबई शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पर लागू होता है, यह भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और तदनुसार, अमान्य है।

नियम 4(ए) इस प्रकार है:-

4. वरीयता:

(ए) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय निम्नलिखित क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी: -

(ए) मूल संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार

(नोट: मूल संस्थान का अर्थ वह मेडिकल कॉलेज है जहां से उम्मीदवार ने अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है)।

(बी) उम्मीदवार जिन्होंने अन्य नगर पालिका से स्नातक किया है बृहन मेडिकल कॉलेज मुंबई में।"

18 जून 1971 के सरकारी संकल्प के तहत बनाए गए नियम 5 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"5.....

..... योग्य उम्मीदवारों में से चयन करते समय उस कॉलेज के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्होंने अपना अंतिम एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण किया। व्यापक विशिष्टताओं और उनके सहायक अनुशासन में उस कॉलेज से परीक्षा।"

बॉम्बे शहर में चार मेडिकल कॉलेज हैं, और बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इन चार मेडिकल कॉलेजों में से तीन बॉम्बे नगर निगम, ई अर्थात् लोकमान्य तिलक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (एलटीएमएमसी), सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज (जीएसएमसी) और टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज (टीएनएमसी) द्वारा संचालित और संचालित किए जाते हैं। बॉम्बे शहर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एकमात्र कॉलेज ग्रांट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) है। प्रमुख तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दाखिल करने के लिए, जिनमें से एफ ये अपीलें उत्पन्न होती हैं। यह कहना पर्याप्त है कि

कुछ उम्मीदवार जिन्हें संबंधित कॉलेजों में एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला था, जहां से उन्होंने एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें कॉलेज के मद्देनजर बॉम्बे शहर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी प्रवेश नहीं दिया गया था- तीन नगर निगम कॉलेजों के संबंध में नियम 4(ए) और जीएमसी, जी महाराष्ट्र सरकार कॉलेज से संबंधित नियम 5 द्वारा प्रदान की गई बुद्धिमान संस्थागत प्राथमिकता। उच्च न्यायालय, जैसा कि पहले ही कहा गया है। नियम 4(ए) और नियम 5 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया और रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी। अत: विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री जी. रामास्वामी ने आग्रह किया है कि डॉ. प्रदीप जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एच एंड अन्य, [1984] 3 एससीआर 942 में इस न्यायालय ने अपनी मंजूरी के पर्याप्त संकेत दिए हैं।

कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता जबकि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह बॉम्बे शहर में नगर निगम कॉलेजों और सरकारी कॉलेज में एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शत-प्रतिशत संस्थागत प्राथमिकता या सीटों के आरक्षण का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसी प्राथमिकता या आरक्षण सीटों के कुछ प्रतिशत के

संबंध में यह काफी स्वीकार्य है और संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान से प्रभावित नहीं होगा।

प्रदीप जैन के मामले में, इस न्यायालय द्वारा जिस प्रश्न पर विचार किया गया है, जैसा कि भगवती, जे. (जैसा कि वह तब था) ने कहा था कि क्या, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप, मेडिकल कॉलेज या उच्च शिक्षा के किसी अन्य संस्थान में प्रवेश की स्थिति है किसी राज्य में उन लोगों तक ही सीमित किया जा सकता है जिनका राज्य के भीतर अधिवास है या जो निर्दिष्ट वर्षों से राज्य के भीतर निवासी हैं या उनके लिए प्रवेश में कोई आरक्षण किया जा सकता है ताकि उन्हें उन लोगों पर प्राथमिकता दी जा सके जो ऐसा नहीं करते हैं। योग्यता के बावजूद, राज्य के भीतर अधिवास या आवासीय योग्यता होनी चाहिए। जो प्रश्न तैयार किया गया है और जिस पर विचार किया गया है, वह प्रथम दृष्टया यह नहीं दर्शाता है कि कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता भी प्रश्न के एक भाग के रूप में शामिल थी। प्रदीप जैन के मामले में यह फैसला सुनाया गया है कि देश के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करके तकनीकी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्रों का चयन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। मेडिकल कॉलेजों या विशिष्ट विषयों में शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों में अधिक मेधावी छात्र उपलब्ध होने पर कम मेधावी छात्रों को

प्रवेश देना। इसलिए, योग्यता की परवाह किए बिना, इस आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले सभी छात्रों को छोड़कर, राज्य के भीतर अधिवास या आवासीय आवश्यकता के आधार पर या विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर थोक आरक्षण दिया गया है। निंदा की गई. न्यायालय ने यह विचार किया कि राज्य के भीतर आवासीय आवश्यकता या संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर सीटों का आरक्षण, किसी भी स्थिति में, अन्य प्रकार के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, खुली सीटों की कुल संख्या के 70 प्रतिशत की बाहरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि भारतीय चिकित्सा परिषद छोटी बाहरी सीमा निर्धारित करती है, तो 70 प्रतिशत आरक्षण को कम करने की आवश्यकता है।

भगवती, जे. की टिप्पणी में जिस संस्थागत प्राथमिकता का उल्लेख किया गया है, वह कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, जिससे हम चिंतित हैं। हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रदीप जैन के मामले में भगवती, जे द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर मजबूत भरोसा जताया है, जिसे नीचे दिया गया है: -

> "इसलिए हमारा विचार है कि जहां तक एम.एस., एम.डी. और इसी तरह के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का सवाल है, यह अत्यधिक वांछनीय होगा कि राज्य के भीतर या

संस्थागत आधार पर निवास की आवश्यकता के आधार पर कोई आरक्षण प्रदान न किया जाए। वरीयता लेकिन, शिक्षा में अवसर की समानता और संस्थागत निरंतरता के व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए, जिसका अपना महत्व और मूल्य है, हम निर्देश देंगे कि हालांकि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता पोस्ट-प्रवेश में आरक्षण के लिए आधार नहीं होगी। वर्तमान परिस्थितियों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटों का एक निश्चित प्रतिशत संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर इस अर्थ में आरक्षित किया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्र को प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। उसी मेडिकल कॉलेजों या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लेकिन संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध खुली सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह बाहरी सीमा जो हम तय कर रहे हैं, वह भी भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उसी तरह से निचले स्तर पर संशोधन के अधीन होगी जैसा कि एमबीबीएस में प्रवेश के मामले में हमारे द्वारा निर्देशित है। अवधि। लेकिन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में

भी, हम निर्देश देंगे कि जहां तक न्यूरो-सर्जरी और कार्डियोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी का संबंध है, संस्थागत प्राथमिकता और प्रवेश के आधार पर भी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अखिल भारतीय आधार पर पूरी तरह से योग्यता के आधार पर अनुदान दिया जाना चाहिए।"

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह आग्रह किया गया है कि एफ प्रदीप जैन के मामले में कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता को मान्यता दी गई है और बरकरार रखा गया है, जैसा कि उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट है। विशेष रूप से अवलोकन से "वर्तमान परिस्थितियों में, सीटों का एक निश्चित प्रतिशत, संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर इस अर्थ में आरक्षित किया जा सकता है कि एक छात्र जिसने मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उसे जी में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है उसी मेडिकल कॉलेजों या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, लेकिन संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध खुली सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।" यह सच है कि मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय के संबंध में उक्त

अवलोकन में "संस्थागत प्राथमिकता" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस अवलोकन को करने में भगवती, जे, के दिमाग में क्या था

कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता किसी भी अवलोकन को उस विशेष मामले के तथ्यों की प्रतियोगिता में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसके संबंध में ऐसा अवलोकन किया गया है। जैसा कि बताया गया है, प्रदीप ले मामले में जिस प्रश्न पर विचार किया गया है वह राज्य के भीतर निवास या आवासीय योग्यता यानी योग्यता के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यह किसी का मामला नहीं था कि सीटों का आरक्षण कॉलेजवार प्रारंभिक वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। मामले में जिस संस्थागत प्राथमिकता पर विचार किया गया वह विश्वविद्यालयवार संस्थागत प्राथमिकता थी न कि कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता। अमरेंद्र नाथ सेन 1 के फैसले से यह भी स्पष्ट है, जिन्होंने एक अलग लेकिन ठोस निर्णय दिया था, कि अदालत के पास एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामलों में कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता के सवालों पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि इस न्यायालय ने प्रदीप के जन के मामले में एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेजों में

सीटों की कॉलेजवाए संस्थागत प्राथमिकता को बरकरार रखा है या मान्यता दी है।

निदामारी महेश कुमार स्टेट ऑफ महाराष्ट्रर्स एंड अदर्स, 1962 एससीसी 534 में इस न्यायालय के बाद के फैसले में स्थिति स्पष्ट की गई है, जो मेडिकल कॉलेजों में सीटों के क्षेत्रवार आरक्षण की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। इसे भगवती ने देख लिया है। सी. जहां वह क्षेत्र जहां से किसी विश्वविद्यालय के छात्र बड़े पैमाने पर आते हैं, चिकित्सा शिक्षा के अवसरों या सक्षम और पर्याप्त चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से पिछड़ा है, यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य होगा, बिना शासनादेश का उल्लंघन किए। समानता खंड उस क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षण या प्राथमिकता का उच्च प्रतिशत प्रदान करता है क्योंकि आरक्षण या प्राथमिकता के बिना इतने पिछड़े क्षेत्र के छात्र शायद ही उन्नत क्षेत्रों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनके पास विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं होंगे। ताकि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में रह सकें। इसके अलावा, यह देखा गया है कि राज्य के लिए प्रत्येक क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज या कॉलेजों में उन लोगों के पक्ष में सीटों के एक निश्चित प्रतिशत के संबंध में आरक्षण या प्राथमिकता प्रदान करना असंवैधानिक नहीं होगा, जिन्होंने वहां के स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाई की

है। उस क्षेत्र में और भले ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत उच्च स्तर पर हो, यह समानता के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन नहीं होगा।

वरीयता के ऐसे आरक्षण के संबंध में जो कारण दिए गए हैं वे यह हैं कि इससे काफी कठिनाई और असुविधा होगी यदि किसी विशेष विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है यदि पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयन बिना किसी योग्यता के आधार पर होता है क्षेत्रवार आरक्षण या प्राथमिकता. बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हो सकते हैं, जिन्हें यदि उनके निवास के पास के मेडिकल बी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता है और सापेक्ष योग्यता के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र के कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है, तो वे ऐसे अन्य में जाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। संसाधनों और सुविधाओं की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा और परिणामस्वरूप, वे मेडिकल पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के वास्तविक अवसर से वंचित हो जाएंगे, भले ही कागज पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया हो। इसके अलावा, यह बताया गया है कि लड़कियों के मामले में कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी क्योंकि यदि वे अपने निवास स्थान के पास के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें स्थित मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। एक अन्य

क्षेत्र जहां छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं और यदि छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध भी हैं। उपलब्ध हैं, तो माता-पिता उन्हें होटलों में भेजने में संकोच कर सकते हैं।

ऊपर उल्लिखित कारणों को छोड़कर, मेडिकल कॉलेजों में कुछ प्रतिशत सीटों के क्षेत्रवार आरक्षण के संबंध में भी। निदामर्ती के मामले में इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि आक्षेपित नियम का प्रावधान, यानी, किसी विशेष विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित स्कूल या कॉलेज के छात्र मेडिकल कॉलेज या कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी अन्य विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र, लेकिन केवल उसी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर मेडिकल कॉलेज या कॉलेजों तक ही सीमित होगा, इसका उद्देश्य कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को सुरक्षा देना था, जिनकी आबादी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है। अन्यथा वे उन्नत क्षेत्रों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते और परिणामस्वरूप, प्रावधान द्वारा किया गया वर्गीकरण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य था। इस प्रकार, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, मेडिकल कॉलेजों में सीटों के क्षेत्रवार आरक्षण को भी इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। प्रदीप जैन के मामले में, केवल इसलिए कि अभिव्यक्ति "संस्थागत प्राथमिकता" का उपयोग मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस जी कोर्स पास करने वाले छात्र के संदर्भ में किया गया है, यह

जरूरी नहीं है कि न्यायालय अपने विचार में था या रख रहा था। नीचे कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता।

इस तर्क के समर्थन में कि कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता या सीटों का आरक्षण इस न्यायालय के विचार में था, अपीलकर्ताओं की ओर से पहले के फैसले पर निर्भरता रखी गई है जगदीश सरन एवं अन्य में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1980] 2 एससीआर 831। उस मामले में, तीन विद्वान न्यायाधीशों में से, कृष्णा अय्यर, जे. ने अपने लिए और चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. पाठक, जे. (जैसा कि उन्होंने) के लिए फैसला सुनाया तब वह कृष्णा लायर, जे. के फैसले से सहमत थे कि रिट याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के कारण बताए। पाठक, जे. के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियों में निहित हैं:

> "यह तर्क से परे नहीं है कि एक छात्र जो अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करता है और अपेक्षित वर्षों की अवधि तक वहां पढ़ाई करता है, उसे स्नातक स्तर पर अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में रहना पसंद करना चाहिए। यह एक मजबूत तर्क है सुविधा, स्थिरता और शैक्षिक माहौल से परिचित होने की, जो देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग आर्थिक और

मनोवैज्ञानिक दबावों के अधीन है। लेकिन सुविधा से कहीं अधिक इसमें शामिल है। एक ही शैक्षिक में शैक्षिक अनुभव के निरंतर फ्रेम के सभी फायदे हैं संस्थान। यह याद रखना चाहिए कि यह अध्ययन का एक पूरी तरह से अलग पाठ्यक्रम नहीं है, जो कि पहले से चला आ रहा है; यह एक विशेष और गहरा अनुभव है। छात्र शिक्षण तकनीकों और छात्रवृत्ति के मानकों से परिचित हो गया है, और अपनी प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को तदनुसार समायोजित किया है। अध्ययन की निरंतरता ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करने में उच्च स्तर की क्षमता सुनिश्चित करती है। कभी-कभी प्रोफेसरों और पाठकों के समान स्टाफ में से कुछ लोग स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी व्याख्यान दे सकते हैं। स्नातक के वर्षों में शिक्षक को छात्र की विशेष ज़रूरतें समझ में आ गई हैं, कि वह कहाँ उत्कृष्टता प्राप्त करता है और कहाँ कमियों को दूर करने के लिए उसे विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मेरे निर्णय में, एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अपने स्नातक को एक निश्चित डिग्री की प्राथमिकता देने का अच्छा कारण है। प्राथमिकता एक उचित वर्गीकरण पर आधारित है और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रदान की जाने

वाली शिक्षा के उद्देश्य से उचित संबंध रखती है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में संहिताबद्ध समानता की अवधारणा का उल्लंघन नहीं किया गया है। कभी-कभी यह कहा गया है कि वर्गीकरण समानता का खंडन करता है। मेरे विचार से, वर्गीकरण समानता के मूल की एक विशेषता है। समानता सुनिश्चित करने में यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, उन लोगों के लिए जो समान रूप से अपने बीच एक वर्ग से अकेले स्थित हैं, और वर्गीकरण नहीं हैयदि इसका घटक आधार संबंधित कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने से उचित रूप से संबंधित है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है। यहां जिस तरह की संस्थागत प्राथमिकता पर विचार किया गया है, वह समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं करती है।"

उपरोक्त टिप्पणियों या कारणों को नहीं पढ़ा जाना चाहिए या इसके तहत नहीं पढ़ा जाना चाहिए- बी इस न्यायालय के निर्धारण के लिए शामिल तथ्यों और प्रश्नों से अलग है। उस मामले के तथ्य फिलहाल बताये जायेंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय में सभी 250 सीटों पर कई स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। दिल्ली के तीन मेडिकल कॉलेजों से हर साल 400 मेडिकल स्नातक निकलते हैं, जिन्हें

स्थानीय अस्पतालों में घरेलू नौकरियाँ मिलती हैं और वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकों को चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से समायोजित नहीं किया जा सका और चूंकि इन स्नातकों को अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया गया था, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर पर कुछ सीटें निर्धारित की थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के मेडिकल स्नातकों के लिए चिकित्सा। विवादित नियम के अनुसार, डी स्नातकोत्तर स्तर पर 70 प्रतिशत सीटें दिल्ली के स्नातकों के लिए आरक्षित थीं और 30 प्रतिशत सीटें दिल्ली के स्नातकों सहित सभी के लिए खुली रखी गई थीं। इसलिए, यह कॉलेजवार आरक्षण का मामला नहीं था, बल्कि उस विश्वविद्यालय के मेडिकल स्नातकों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत मेडिकल कॉलेजों में 70 प्रतिशत सीटों का आरक्षण था। कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता या सीटों के आरक्षण का सवाल ही नहीं उठा, न ही जगदीश सरन के मामले में इस पर बहस की गई या निर्णय लेने की मांग की गई। यह सच है कि तथ्यों के संदर्भ और उस मामले में शामिल प्रश्न के संदर्भ के बिना पाठक, जे. का

अवलोकन, कुछ हद तक अपीलकर्ताओं के विवाद का समर्थन कर सकता है, लेकिन उस मामले में शामिल तथ्य और प्रश्न के संदर्भ में विवाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कुछ विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ हैं जो कॉलेजवार आरक्षण को उचित ठहराते हैं जैसा कि लागू नियम 4 (ए) और 5 द्वारा प्रदान किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक परीक्षाओं के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं, कुल अंकों के 50 प्रतिशत वाली व्यावहारिक परीक्षाएँ अलग-अलग कॉलेजों द्वारा आयोजित की जाती हैं। वकील का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में इन चार कॉलेजों से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता की तुलना और मूल्यांकन एमडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से करना मुश्किल है। यह निवेदन विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बेज़ द्वारा भी किया गया है।

हमें खेद है, हम इस तरह के विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रत्येक कॉलेज में व्यावहारिक परीक्षाएं चार परीक्षकों के एक समूह द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिसमें एक ही कॉलेज से एक आंतरिक परीक्षक, अन्य तीन में से एक बाहरी परीक्षक शामिल होता है। कॉलेज और बंबई के बाहर से दो बाहरी परीक्षक। इस

प्रकार, एक आंतरिक परीक्षक को छोड़कर, तीन अन्य परीक्षक बाहरी परीक्षक हैं और उन सभी परीक्षकों को संभवतः बी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये परीक्षक उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले हैं और हम यह समझने में असफल हैं कि वे व्यावहारिक परीक्षाओं में छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक से क्यों विचलित होंगे। इसलिए, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि ऐसी व्यावहारिक परीक्षाओं में परीक्षा का मानक और छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन हर कॉलेज में अलग-अलग होता है। दरअसल, इस तर्क के समर्थन में हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि एमबीबीएस प्रैक्टिकल परीक्षाओं में कॉलेजों द्वारा अलग-अलग मानक अपनाए जाते हैं। यह तर्क भी उतना ही अप्रासंगिक है कि संस्थागत प्राथमिकता के कारण, विभिन्न कॉलेजों द्वारा दिए गए अलग-अलग अंक छात्रों को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक ही कॉलेज में छात्र की सापेक्ष योग्यता है जो स्नातकोत्तर छात्रों के चयन में मायने रखती है। हमें इस आशंका का कोई औचित्य नहीं मिलता है कि यदि संस्थागत प्राथमिकता को हटा दिया जाता है और विश्वविद्यालय के सभी उम्मीदवारों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है, तो कमजोर पड़ने और अवांछनीय दौड़ की एक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है जो परीक्षा प्रणाली का मजाक उड़ाएगी और पागलपन पैदा करेगी। दूसरे कॉलेजों से आगे निकलने की होड़ यह आशंका लोकमान्य

तिलक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में व्यक्त की है।

कॉलेजवार संस्थागत वरीयता के औचित्य में एक और आधार जिस पर डीन ने अपने हलफनामे में भरोसा किया है और अपीलकर्ताओं की ओर से हमारे सामने आग्रह किया है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के पैटर्न के संबंध में सुविधाएं कॉलेज से कॉलेज में भिन्न होती हैं। प्रत्येक महाविद्यालय से संबद्ध। उदाहरण के तौर पर, यह कहा गया है कि लोकमान्य तिलक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में आघात के मामलों (दुर्घटनाओं और चोटों) का भार सबसे अधिक है, ऐसे मामलों की संख्या अन्य तीन से जुड़े अस्पताल की तुलना में बहुत अधिक है। कॉलेज. लोकमान्य तिलक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के स्नातक छात्रों को इन मामलों का व्यापक अनुभव होगा और वे सर्जरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट के लिए कहीं अधिक उपयुक्त होंगे जहां उन्हें वास्तव में एक छात्र की तुलना में इन मामलों से निपटना होगा। किसी अन्य कॉलेज का. यह मानते हुए भी कि ऊपर बताए गए तथ्य सही हैं, हमें नहीं लगता कि यह संस्थागत प्राथमिकता के समर्थन में कोई आधार है। यह विश्वविद्यालय है जिसके संबंध में एक मानक बनाए रखना आवश्यक है।

इससे संबद्ध महाविद्यालयों में एक विषय। यह विश्वविद्यालय का मामला नहीं है कि इसके द्वारा निर्धारित मानक विभिन्न कॉलेजों में बनाए

नहीं रखा जाता है या किसी विशेष कॉलेज का मानक किसी विशेष विषय में दूसरे कॉलेज की तुलना में अधिक है। ऐसा हो सकता है कि लोकमान्य तिलक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में दुर्घटना और चोट के मामलों की संख्या अन्य कॉलेजों से जुड़े बी अस्पतालों में ऐसे मामलों की संख्या से अधिक हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है या निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अन्य महाविद्यालयों के छात्र लोकमान्य तिलक के छात्रों की तुलना में शल्य चिकित्सा में कमजोर या कम मेधावी होंगे मेमोरियल मेडिकल कॉलेज. इस संबंध में विवाद निराधार है पदार्थ और अस्वीकार कर दिया गया है।

आइए अब हम संविधान के अनुच्छेद 14 के दृष्टिकोण से कॉलेजवार संस्थागत वरीयता के प्रश्न की जांच करें। आक्षेपित नियमों के अनुसार, प्रत्येक विशेष कॉलेज के छात्रों के साथ उस कॉलेज से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अन्य सभी छात्रों को छोड़कर एक वर्गीकरण बनाने की मांग की गई है। अन्य कॉलेजों से एमबीबीएस की डिग्री। संविधान के अनुच्छेद 14 के अर्थ के अंतर्गत एक वर्गीकरण को स्वीकार्य बनाने के लिए, दो परीक्षणों को संतुष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात्, (1) कि एक समझदार अंतर है जो एक साथ समूहित व्यक्तियों को उन लोगों से अलग करता है जो इससे बाहर रह गए हैं। समूह; और (2) कि विवादित नियमों द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। आक्षेपित नियमों

द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य स्पष्ट रूप से डी के लिए योग्यता को प्राथमिकता देना है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और कम मेधावी उम्मीदवारों को बाहर करना। यह वर्तमान में प्रदर्शित किया जाएगा कि दोनों परीक्षण संतुष्ट नहीं हैं तात्कालिक मामला. इस संबंध में हम नीचे निम्नलिखित सारणी दे रहे हैं इनमें से प्रत्येक में उपलब्ध सीटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण कुछ विषयों में चार कॉलेज।

कॉलेज	एलटीएमएमसी	टीएनएमसी	जीएसएमसी	जीएमसी
छात्र इन्टेक	100	100	100	
अनुशासन				
1. एमडी2	1		5	3+1(R)
ओबीएस व				
जीवाईएन				
2. एम.एस.2	1		2	1
हड्डी रोग				
3. एम.एस.4	2		3	3+1(R)
जनरल सर्जरी				
4. एम.डी.4	3		3	3+1(R)
जनरल				
मेडिसिन				

सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज (जीएसएमसी) में प्रसूति एवं स्त्री रोग में पांच सीटें और टोपीवाला नेशन मेडिकल कॉलेज (टीएनएमसी) में एक सीट है। कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता प्रदान करने वाले विवादित नियमों के मद्देनजर, सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में पांच सीटें इसके पांच छात्रों को आवंटित की गईं। इन पांच छात्रों में से, डॉ. गणपत सावंत ने एमबीबीएस परीक्षा में 150 अंक हासिल किए और अन्य चार उम्मीदवारों ने 118 और 128 के बीच अंक हासिल किए। उत्तरदाताओं देवकुमार ठुकराल और डॉ. सुमीत गोडाम्बे, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज के दोनों छात्रों ने एमबीबीएस परीक्षा में क्रमशः 140 और 143 अंक प्राप्त किए। हालाँकि, उन्हें उनके कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में केवल एक सीट थी और वह सीट उस कॉलेज के एक छात्र को आवंटित की गई थी, जिसने एमबीबीएस परीक्षा में 156 अंक प्राप्त किए थे। इस प्रकार, यद्यपि डॉ. अंजलि देवकुमार ठुकराल और डॉ. सुमीत गोडाम्बे ने उक्त जी.एस. मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उक्त डॉ. गणपत सावंत को छोड़कर, उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता का दृश्य। इसी प्रकार, अन्य विषयों के संबंध में कई मेधावी छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका, भले ही उन्होंने लागू नियमों के आधार पर स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वालों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए

हों। इस प्रकार, पेटेंट भेदभाव है। चूँकि कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अधिक अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। कॉलेजवार संस्थागत वरीयता के माध्यम से वर्गीकरण के लिए कोई समझदार अंतर नहीं है, जैसा कि प्रत्येक कॉलेज के संबंध में पसंदीदा उम्मीदवारों को ऐसे वर्गीकरण से बाहर किए गए उम्मीदवारों से अलग करने वाले आक्षेपित नियमों द्वारा प्रदान किया गया है। इस तरह के वर्गीकरण या कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता से, योग्यता का त्याग किया गया है, इसे प्राथमिकता देना तो दूर की बात है। जब इन सभी कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय एक ही है, पाठ्यक्रम, परीक्षा का मानक और यहां तक परीक्षक भी समान हैं, तो योग्यता के क्रम को छोड़कर, उसी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। योग्यता शिक्षण संस्थानों के स्तर को काफी हद तक प्रभावित करती है। ऐसी परिस्थितियों में, कॉलेज-वार संस्थागत प्राथमिकता का समर्थन नहीं किया जा सकता है और, यह पहले ही देखा जा चुका है कि इस न्यायालय ने ऐसी प्राथमिकता को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी है।

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम डॉ. अशोक कुमार गुप्ता और अन्य, [1989] 1 एससीसी 93 एक ही विश्वविद्यालय के तहत राजस्थान में पांच मेडिकल कॉलेजों के संबंध में कॉलेज-आधारित संस्थागत प्राथमिकता का मामला है। विश्वविद्यालय के विवादित अध्यादेश में अंकों के कुल योग का

5 प्रतिशत जोड़ने का प्रावधान है जो कि बनता हैउस विशेष मेडिकल कॉलेज पर निर्भर वरीयता के अर्थ में संस्थागत वरीयता के माध्यम से 137.5 अंक, जहां संबंधित उम्मीदवार ने अपनी अंतिम एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है। उस मामले में इस कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और लागू अध्यादेश को रद्द कर दिया गया है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने डॉ. बी अशोक कुमार गुप्ता के मामले को वर्तमान मामले से अलग करने की मांग की। हमें नहीं लगता कि उक्त मामला उस मामले से अलग है जिससे हम चिंतित हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में कॉलेजवार या कॉलेज-आधारित संस्थागत प्राथमिकता का प्रश्न शामिल है। यह कहा गया है कि डॉ. अशोक कुमार गुप्ता के मामले में कॉलेजवार संस्थागत वरीयता देने के लिए अपनाई गई पद्धति या पद्धति मौजूदा मामले से अलग है, लेकिन, हमारी राय में, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। जहां तक शैक्षणिक संस्थानों का सवाल है, जब तक मेधावी उम्मीदवारों को बाहर करने के मजबूत कारण न हों, योग्यता के क्रम के अलावा कोई भी प्राथमिकता संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। इसलिए, लागू किए गए नियम भेदभावपूर्ण हैं और तर्कसंगत वर्गीकरण के परीक्षणों को पूरा नहीं करते हैं और, उतना ही, कायम नहीं रखा जा सकता है।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि बॉम्बे नगर निगम को अपने द्वारा प्रायोजित तीन कॉलेजों को चलाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए इन तीन कॉलेजों में छात्रों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करना। यदि इस तरह के आरक्षण की अनुमति दी जाती है, तो महाराष्ट्र सरकारी कॉलेज, अर्थात् ग्रांट मेडिकल कॉलेज के छात्रों को तीन नगर निगम कॉलेजों में से किसी में भी प्रवेश नहीं मिलेगा, भले ही छात्र या उनमें से कुछ ने एमबीबीएस कोर्स पास कर लिया हो। सरकारी कॉलेजों के छात्र उन छात्रों से अधिक मेधावी हैं जिनके लिए नगर निगम कॉलेजों में सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। यह आग्रह किया जाता है कि जहां तक म्यूनिसिपल कॉलेजों का सवाल है, यह कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता का मामला नहीं होगा और बॉम्बे नगर निगम को म्यूनिसिपल कॉलेजों के छात्रों को प्राथमिकता देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकारी कॉलेज के छात्रों का बहिष्कार. हमारी राय में यह विवाद बिना किसी तथ्य के है। हो सकता है कि बंबई नगर निगम को अपने द्वारा संचालित कॉलेजों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन यह नगर निगम कॉलेजों और उससे संबद्ध सरकारी कॉलेजों के छात्रों के बीच भेदभाव करने का कोई आधार नहीं होगा। विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से। इस तरह के भेदभाव से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसे किसी भी तर्कसंगत आधार पर उचित ठहराया जा सके।

इस तरह के आरक्षण या वरीयता को भी एच की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि अनुमति दी जाती है, तो नियमों के नियम 5 के तहत बनाया गया है।18 जून, 1971 का सरकारी संकल्प तब तक मान्य रहेगा जब तक ग्रांट मेडिकल कॉलेज के छात्रों को केवल एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन, जो छात्र उस कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सके, वे नगर निगम कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। हम एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में इस तरह के भेदभाव की अनुमति देने में असमर्थ हैं।

एक अन्य आधार जिस पर कॉलेजवार संस्थागत वरीयता को विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उचित ठहराने की मांग की गई है वह संस्थागत निरंतरता के आधार पर है। संस्थागत निरंतरता के इस आधार के समर्थन में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जगदीश सरन के मामले में पाठक, जे. की टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जो पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है। यह कॉलेजवार संस्थागत प्राथमिकता या संस्थागत निरंतरता का मामला नहीं था, और उक्त टिप्पणियों को उस अर्थ में नहीं, बल्कि एक ही विश्वविद्यालय में संस्थागत निरंतरता के अर्थ में समझा जाना चाहिए।

कॉलेजवार संस्थागत वरीयता के प्रश्न पर विचारशील विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि सीटों की ऐसी प्राथमिकता या आरक्षण की

अनुमति नहीं है और उच्च न्यायालय ने बॉम्बे द्वारा बनाए गए दोनों नियम 4 (ए) को सही ढंग से खारिज कर दिया है। नगर निगम और सरकारी संकल्प के तहत बनाए गए नियम 5 का हिस्सा, यानी केवल स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित बॉम्बे शहर में ग्रांट मेडिकल कॉलेज में इसके आवेदन के संबंध में। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिन छात्रों को विवादित नियमों के अनुसार स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उनके प्रवेश में हस्तक्षेप या परेशान नहीं किया जाएगा।

इस स्थिति में, हम सी.एम.पी. में आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ललित की दलील पर विचार कर सकते हैं। 1988 की संख्या 20748 में उन्हें 1988 की सिविल अपील संख्या 2792 में पक्ष-प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की प्रार्थना की गई है। हमें नहीं लगता कि उन्हें अपील में पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा। श्री ललित द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि जिन आवेदकों ने नगर निगम कॉलेजों से डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें नगर निगम के किसी भी कॉलेज में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के क्रेडिट के साथ एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र माना जाना चाहिए। हमें राज्य सरकार और बंबई नगर निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बताया है कि यदि विवादित नियमों को रद्द कर दिया जाता है, तो उन्हें इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप नए नियम बनाने होंगे और, जैसा कि

हमने निर्देश दिया है।विवादित नियमों के अनुसार स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों के प्रवेश में बाधा डालने के लिए, हम आवेदकों द्वारा की गई प्रार्थना को काफी उचित मानते हैं और तदनुसार, निर्देश देते हैं कि जिन आवेदकों ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, वे उत्तीर्ण होने के बाद नगर निगम कॉलेजों में प्रवेश लें। एमबीबीएस परीक्षा के बाद, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के क्रेडिट के साथ नगर निगम के किसी भी बी पाल कॉलेज में स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री तारकुंडे का कहना है कि कुछ उत्तरदाताओं के प्रवेश के मामले, जिन्हें उनकी पसंद की कुछ विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया है। विवादित नियमों पर महाराष्ट्र राज्य और ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम द्वारा विचार किया जा सकता है, यदि सीटें उपलब्ध हैं, या तो नगर निगम कॉलेजों में या ग्रांट मेडिकल कॉलेज में, जो एक सरकारी कॉलेज है। हमारी राय में, प्रार्थना काफी उचित है और महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे नगर निगम को उनके सी के प्रश्न पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है डी प्रवेश, बशर्ते सीटें उपलब्ध हों। उक्त प्रतिक्रिया के नाम- डेंट और उनकी पसंद के संबंधित विषय नीचे दिए गए हैं:

1. डॉ. अंजली देओकुमार ठुकराल	एम.डी. स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान
2. डॉ. अतुल जयवंत गायतोंडे	एमएस हड्डी रोग
3. डॉ. नरेश कनयालाल नवानी	एमएस जनरल सर्जरी
4. डॉ. अन्ना कोशी जोसेफ़	एम.डी. जनरल मेडिसिन
5. डॉ. वैशाली रमणीक दोशी	एम.डी. जनरल मेडिसिन

इन मामलों से अलग होने से पहले, हम अपीलकर्ताओं की ओर से की गई एक दलील का निपटारा कर सकते हैं। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि विवादित नियम 4(ए) और विवादित नियम 5 को आंशिक रूप से रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में बर्खास्तगी के लिए कुछ वैकल्पिक तरीकों को अपनाते हुए जी फ्रेम नियम बनाने का निर्देश दिया है। अगले वर्ष के लिए, जैसा कि फैसले में कहा गया है। उक्त निर्देश उच्च न्यायालय के सुझावों की प्रकृति में प्रतीत होते हैं, और अपीलकर्ता उक्त चार कॉलेजों में स्नातकोत्तर एम.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंबई शहर में संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान के अनुरूप और इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में और नियम बनाते समय, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के ए सुझावों को ध्यान में रख सकते हैं।

परिणामतः उपरोक्त निर्देशों के अधीन अपीलें बर्खास्त कर दिए जाते हैं. हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 8883/1988 और रिट याचिका (सिविल) संख्या. 1988/1253

उपरोक्त कारणों से, विशेष अनुमति याचिका और रिट याचिका विफल हो जाती हैं और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मोनिका धनोल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।